

## पर्यावरण और हम

यह एडिटरियल 08/06/2022 को 'हदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "Climate and Us | A movement that puts a spotlight on West's wasteful consumption" लेख पर आधारित है। इसमें पश्चिमी देशों के अपव्ययी उपभोग को उजागर करने के लिये और जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत की समस्याओं के समाधान के लिये भारत द्वारा की गई एक विशेष पहल के बारे में चर्चा की गई है।

## संदर्भ

हाल ही में [वैश्व पर्यावरण दविस](#) के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 'पर्यावरण के लिये जीवनशैली आंदोलन' [Lifestyle for the Environment (LiFE) Movement] वैश्विक पहल लॉन्च की गई। यह आंदोलन विकसित और विकासशील देशों के उपभोग पैटर्न के साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी, प्रतियोगिता CO2 उत्सर्जन और कार्बन स्पेस जैसे पहलुओं को वैश्विक ध्यान के केंद्र में लाने का एक प्रयास है।

## वैश्विक जीवनशैली आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं?

- यह पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली पर शक्तिवादों, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से विचारों एवं सुझावों को आमंत्रित करने के लिये एक वैश्विक आह्वान की शुरुआत करेगा और इस क्रम में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को जीने के तरीके में रूपांतरण के लिये प्रेरित करेगा।
- इनमें जल, परिवहन, आहार, बजिली, पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के संबंध में व्यक्तियों, घरों और समुदायों पर लक्षित व्यवहार-परिवर्तन समाधान भी शामिल हैं।
- यह जलवायु संकट के संबंध में स्थानीय सामाजिक समाधानों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सोशल मीडिया नेटवर्क की शक्ति का लाभ उठाएगा।
- ऐसे नवोन्मेषी समाधानों पर भी विचार आमंत्रित किए जाएँगे जो पारंपरिक, जलवायु-अनुकूल अभ्यासों को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देते हैं और/या उन समुदायों के लिये आजीविका विकल्प का निर्माण करते हैं जो जलवायु-अनुकूल उत्पादन की ओर संक्रमण के साथ अपनी आजीविका खोने का खतरा रखते हैं।
- किसी भी ऐसे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और/या स्थानीय सर्वोत्तम अभ्यासों का पालन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें जलवायु कार्रवाई से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिये व्यावहारिक रूप से संवर्द्धित किया जा सकता है।

## हमें इस प्रकार के आंदोलन की आवश्यकता क्यों है?

- **COP26** ग्लासगो जलवायु सम्मेलन के ग्लासगो संधि के प्रारूपण के दौरान विकसित और विकासशील देशों के बीच नमिन्लखित कुछ विषयों पर संघर्ष की स्थिति बनी थी-
  - **ऐतिहासिक उत्तरदायित्व**: यह औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से विकसित विश्व द्वारा किये गए ऐतिहासिक उत्सर्जन को संबोधित करने का प्रयास करता है,
  - **कार्बन उपनिवेशवाद**: 'समान विचारधारा वाले विकासशील देश' (LMDC)—जिसमें भारत और चीन भी शामिल हैं, के अनुसार विकसित देश 'कार्बन उपनिवेशवाद' (Carbon Colonialism) का प्रदर्शन कर रहे हैं।
    - इसका आशय यह है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति 'साझा कति वभिदति उत्तरदायित्व' (Common But Differentiated Responsibility- CBDR) के सिद्धांत का पालन करने के बजाय विकसित देश विकासशील देशों पर तत्काल शुद्ध-शून्य लक्ष्यों की घोषणा करने का दबाव डाल रहे हैं अथवा 5 डगिरी वैश्विक तापमान लक्ष्य प्राप्ति के संबंध में अपने पक्ष में झुकी वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि विश्व के एक बड़े हिस्से की विकासगत आवश्यकताओं की पूरी तरह से उपेक्षा कर रहे हैं।
  - हाल ही में स्टॉकहोम +50 सम्मेलन (जो ऐतिहासिक स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था) में प्रमुख अनुशासकों के वक्तव्य में भी उपभोग और अपव्ययी दोहन के महत्त्वपूर्ण विषय पर कुछ भी नहीं कहा गया।
    - इसके कारण, ऐतिहासिक उपभोग पैटर्न के प्रति जिवाबदेही का अभाव है।

## CBDR क्या है?

- 'साझा कृति विभिति उत्तरदायित्व' (कभी-कभी 'और संबंधित क्षमताओं' वाक्यांश के साथ) अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सदिधांत है जिसका आशय है कि विभिन्न देशों के पास जलवायु परिवर्तन जैसे सीमा-पारीय पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने की अलग-अलग क्षमताएँ और उत्तरदायित्व हैं। यह सदिधांत नमिनलखित दो आवश्यकताओं में संतुलन का प्रयास करता है:
  - पर्यावरणीय वनिाश और इसके शमन के लिये सभी राज्यों द्वारा व्यक्तगित उत्तरदायित्व ग्रहण करने की आवश्यकता; और
  - यह चहिनति करने की आवश्यकता कि समस्या के लिये सभी राज्य एकसमान रूप से ज़मिमेदार नहीं हैं, न ही कार्रवाई में एकसमान रूप से सक्षम हैं।

## अनुलग्नक-1 और गैर-अनुलग्नक-1 देश

- अनुलग्नक-1 पक्षकारों में वे औद्योगिक देश शामिल हैं जो वर्ष 1992 में 'आर्थिक सहयोग और विकास संगठन' (OECD) के सदस्य थे और वे देश जो EIT (Economies in Transition) पक्षकार थे। इनमें रूसी संघ, विभिन्न बाल्टिक राज्य और विभिन्न मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय राज्य शामिल हैं।
- गैर-अनुलग्नक-1 पक्षकार अधिकांशतः विकासशील देश हैं। विकासशील देशों के कुछ समूहों को विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रती संवेदनशील माना गया है, जिनमें नचिले तटीय क्षेत्रों वाले देश और मरुस्थलीकरण एवं सूखा-प्रवण देश शामिल हैं।
- अन्य अल्पविकसित देश (LDC), जो जीवाश्म ईंधन उत्पादन और वाणज्य से प्राप्त आय पर अत्यधिक निर्भर हैं, जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया उपायों के संभावित आर्थिक प्रभावों के प्रती अधिक भेद्यता रखते हैं। जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन उन गतविधियों पर बल देता है जो इन संवेदनशील देशों की विशेष आवश्यकताओं और चिंताओं के समाधान का वादा करती हैं, जैसे नविश, बीमा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

## भारत द्वारा उजागर की गई विभिन्न असमानताएँ

- प्रती व्यक्त उत्सर्जन और संसाधन उपभोग में व्यापक अंतर है।
- 'क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर' (जलवायु कार्रवाई में इक्विटी का आकलन करने के लिये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड) के अनुसार विभिन्न देशों का प्रती व्यक्त उत्सर्जन इस प्रकार है-
  - ऑस्ट्रेलिया - प्रती व्यक्त 22tco2eq (tonne of CO2 equivalent) या CO2 उत्सर्जन प्रती व्यक्त भीटरकि टन
  - संयुक्त राज्य अमेरिका - 20.2 tco2eq प्रती व्यक्त
  - भारत - 2.4 tco2eq प्रती व्यक्त
  - ब्राज़ील - 5.3 tco2eq प्रती व्यक्त
- विभिन्न देशों के प्रती व्यक्त संसाधन उपभोग से यह भी पता चलता है कि वर्ष 2019 में अमेरिका और अन्य विकसित देशों में प्रती व्यक्त बजिली की खपत सबसे अधिक थी।
- क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर द्वारा वैश्विक कार्बन बजट का एक इंटरैक्टिव मैपिंग भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विभिन्न देशों द्वारा वैश्विक बजट में अब तक उपयोग किये जा चुके उनके हिससे के अनुरूप उनका वर्गीकरण किया गया है।
- यह दर्शाता है कि अधिकांश अनुलग्नक-1 देशों ने अपने उचित हिससे से अधिक का उपभोग कर लिया है और ऋण में हैं जबकि गैर-अनुलग्नक 1 देशों ने अभी तक अपने हिससे का उपभोग नहीं किया है और क्रेडिट की स्थिति रखते हैं।
- यह विकसित देशों में नरिणय लेने की कमी या कार्रवाई करने की अनच्छा और नीतिगतहीनता की स्थिति की पुष्टि करता है।

## आगे की राह

- नीतिआयोग तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की देखरेख में कार्यान्वित LiFE आंदोलन को वैश्विक स्तर पर भागीदारी और समर्थन प्राप्त हो रहा है। नीतिआयोग ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व संसाधन संस्थान (WRI), सेंटर फॉर सोशल एंड बहिवियर चेंज (CSBC) और बलि एंड मेलिडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) की भागीदारी के साथ विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों के लिये दुनिया भर से विचार आमंत्रित किये हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पहल की वर्युअल लॉन्चिंग के अवसर पर बलि गेट्स (बलि एंड मेलिडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष), लॉर्ड निकोलस स्टर्न (ग्रंथम रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष), प्रो. कैस सनस्टीन (हार्वर्ड में रॉबर्ट वाल्मसली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक), इंगर एंडरसन (UNEP के विश्व प्रमुख); डेविड मलपास (विश्व बैंक के अध्यक्ष) जैसे गणमान्य लोग उपस्थित थे जो व्यक्तियों के साथ ही विभिन्न समुदायों एवं समाजों पर एक बड़ा प्रभाव रखते हैं और नशिचय ही इससे लोगों से संलग्नता बढ़ाने में मदद मलिंगी।
- असमानताओं को उजागर करने और नवोन्मेषी समाधानों के साथ बदलाव लाने की ज़रूरत है।
- यह आंदोलन भारत के अंदर असमानताओं को उजागर करने और उन्हें संबोधित करने का भी एक अवसर प्रदान कर सकता है
  - सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन के अनुसार 71 प्रतिशत भारतीय स्वस्थ आहार ग्रहण कर सकने का सामर्थ्य नहीं रखते।
  - इसके अनुसार एक औसत भारतीय व्यक्त के आहार में पर्याप्त फल, सबजियाँ, फलियाँ, मेवे और साबुत अनाज का अभाव होता है;
  - देश के अधिकांश भागों में स्वच्छ जल और पर्यावरण तक पहुँच का भी संकट मौजूद है।
- भारत में लाखों गरीब लोगों की सेहत और आजीविका को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- कोयले पर निर्भर राज्यों के उपयुक्त संक्रमण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये, जो जलद ही उद्योग और नौकरियों में एक बड़े संक्रमण से गुज़र सकते हैं।

**अभ्यास प्रश्न:** "भारत के नेतृत्व में शुरू हुए वैश्विक जीवनशैली आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रकाश डालें और आपके अनुसार इन समस्याओं के क्या समाधान हो सकते हैं?"

